

# ‘अप्प दीपो भव’ वायस ऑफ बुद्ध

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15  
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15  
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 30 जून, 2013

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ० उदित राज (राम राज) चैयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल गेव रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

वर्ष : 16

अंक 15

पाक्षिक

द्विभाषी

16 से 30 जून, 2013



## मादक पदार्थों का श्रेवण ठ करे

-गोतम बुद्ध



# एफवाययूपी के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन



**(बायें से दायें) मंच पर बैठे आमा देव, पाल दिवाकर, डॉ. उदित राज, राम विलास पासवान, सुभाषिनी अली, डॉ. प्रेम सिंह, मो. खालिक एवं अन्य।**

ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (एससी/एसटी/ओबीसी/लेफ्ट) (जेएफडीई) की ओर से 22 जून को जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। यह प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए जा रहे चार वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाययूपी) के विरोध में किया गया। प्रदर्शन को मुख्य रूप से राम विलास पासवान, डॉ० उदित राज, आमा देव, हैनी बाबू, राजेन्द्र सच्चर, सुभाषिनी अली एवं निलोत्पल बसु (सीपीएम) ने सम्बोधित किया। श्री राम विलास पासवान ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जवाब भी आया, फिर भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। गुपचुप रूप से चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू कर दिया और अब लोगों को धीरे-धीरे पता लगने लगा है। सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने कहा कि इससे सर्वाधिक रूप से लड़कियां प्रभावित होंगी। यदि सबसे ज्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है तो महिला वर्ग को, लेकिन उसके विपरीत ही सरकार कर

रही है। जहां भी, जब भी, जैसे भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके पक्षधर कहते हैं कि चूंकि यह अमरीका में लागू है, इसलिए यहां भी शुरू हो रहा है। निलोत्पल बसु ने कहा कि इस शिक्षा नीति से सर्वाधिक रूप से गरीब प्रभावित होंगे। अब यह मुद्दा केवल विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं रहा बल्कि समाज से इसका सारोकार हो गया है। यह आश्चर्य की बात है कि वर्तमान केंद्र की सरकार कांग्रेस की है और 1986 में उसी के पूर्व नेता श्री राजीव गांधी ने ही 10+2+3 की शिक्षा नीति बनायी थी। कि स अधिकार के तहत कुलपति ने इसे 10+2+4 कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के

कुलपति द्वारा यह धृष्टता की जा रही है कि एफवाययूपी के खिलाफ बोलने का आशय है स्वायत्तता में हस्तक्षेप। जबकि वास्तविकता यह है कि कुलपति ने संसद और मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। डॉ० उदित राज, संयोजक,

जेएफडीई ने कहा कि अब यह आंदोलन देशव्यापी होगा। आज के प्रदर्शन में शिक्षक एवं विद्यार्थियों से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। यह सीधा संदेश देता है कि अब यह मामला विश्वविद्यालय एवं कॉलेज तक ही सीमित नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार एक कुलपति के बहकावे में क्यों आ गयी? भाजपा, जदयू, सीपीएम, सीपीआई, एलजेपी आदि राजनैतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरुद्ध इसलिए हैं कि चार वर्ष का बीए ऑनर्स का छात्र दूसरे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर में कैसे प्रवेश लेगा और दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र

दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश पा सकेंगे? एफवाययूपी की पठन-सामग्री दूसरों से कैसे मेल खाएगी, दो तरह के बीए करने वाले छात्रों को रोजगार लेने में कैसे नहीं असुविधा होगी? ग्रामीण, गरीब, दलित एवं पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्र को गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम से तीन तरह की डिग्री मिलेंगी- दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर बैचलर और चार वर्ष पूरा करने पर ऑनर्स जिससे छात्रों में हीन भावना पैदा होगी व शिक्षा जगत में असमानता बढ़ेगी। यह भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय अन्य 700 विश्वविद्यालयों के ही समान है न कि यह अनोखा है जैसा इस समय दिखाने की कोशिश की जा रही है।



एफवाययूपी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर मौजूद अपार भीड़ का एक दृश्य।

# दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों को भागीदारी दिलाने हेतु सम्मेलन संपन्न

पी. सी. कुरील

गत् दिनों 23 जून को राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, पारख महासंघ एससी/एसटी परिसंघ, पिछड़ा समाज महासभा, सविता-सल्मानी समाज महासभा, आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी संगठन, उत्तर प्रदेश ब्रिज कार्पोरेशन कर्मचारी परिषद, उत्तरप्रदेश सचिवालय एसटी / एससी अधिकारी कर्मचारी संघ, रिहाई मंच, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच इत्यादि संगठन ने शासन-प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, राज्यसभा, विधान परिषद व निजी क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों को आबादी के आधार पर भागीदारी दिलाने को लेकर लखनऊ के सहकारिता भवन में संयुक्त आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री पी. सी. कुरील ने की। सम्मेलन का संचालन अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री भवननाथ पासवान ने किया वहीं मुख्य विचारक कौशल किशोर (पूर्व राज्य मंत्री, यूपी सरकार व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पारख महासंघ) ने अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता वाई. एस. लोहित, वरिष्ठ एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स व विशिष्ट अतिथि शाइस्ता अम्बर (अध्यक्ष, महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) सम्मेलन में उपस्थित थीं।

दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों के सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी से अब तक दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता में बैठे लोग मजबूत लोकतंत्र निर्माण का मजबूत भारत की कल्पना सामने लाकर सत्ता में बैठ आम जनता को इंसान की नजर से नहीं जाति की नजर से देखते हैं। जिसके कारण सभी जाति व धर्म के लोगों को सत्ताधारी जातिवादी लोग आबादी के आधार पर भागीदारी न देकर केवल अपनी जाति के लोगों को शासन व प्रशासन में भागीदारी देते हैं बाकी लोगों की अनदेखी करते हैं।

दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों के इस संयुक्त सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो सांसद व विधायक दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों को सभी क्षेत्रों में आबादी के आधार पर भागीदारी देने के सवाल पर चुप्पी साधकर गुंगे बने बैठे हैं। ऐसे विधायकों व सांसदों को दलित, पिछड़े व मुसलमान मतदाता वोट न दें और चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों का बहिष्कार करे चाहे वह किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों।

इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया

गया कि तीन माह में पूरे प्रदेश में भागीदारी रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश के दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों का अधिकार व भागीदारी दिलाने का जन जागरण किया जायेगा और इसके बाद पूरे प्रदेश के सभी कार्यालयों में दलित, पिछड़े व मुस्लिम कर्मचारी व अधिकारी एक दिन का सांकेतिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश में मंडल व जिले स्तर पर मीटिंग करके लखनऊ में एक राज्यव्यापी भागीदारी लाओ रैली की जाएगी।

दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों के इस सम्मेलन में वर्तमान सरकार द्वारा दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों पर किए जा रहे उत्पीड़न की भी तीखी निंदा की गई। सम्मेलन में दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों को भागीदारी दिलाने के सभी समर्थकों को एक मंच पर आने की अपील की गई और जो लोग एक मंच पर आने से कतरा रहे हैं, उनकी इस सम्मेलन में सभी वक्तागणों ने निन्दा करते हुए कहा कि भागीदारी दिलाने के आंदोलन को ऐसे लोग जो एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। सम्मेलन में इसरार उल्ला सिद्दीकी (प्रदेश महासचिव, इंडियन जस्टिस पार्टी), शुएब अहमद (एडवोकेट, रिहाई मंच), राम सिंह यादव (राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल मुस्लिम लीग), जैदा अहमद फारूकी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रिहाई मंच), राजू यादव (उपाध्यक्ष, रिहाई मंच), हारिश सिद्दीकी (अध्यक्ष, नेशनल पीस फेडरेशन), शाहनवाज (प्रवक्ता, रिहाई मंच), लालजीत यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ), एहसानुल हक मलिक (राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा समाज महासभा), शिवनारायण कुशवाहा (राष्ट्रीय महासचिव, पिछड़ा समाज महासभा), जीतू राम रत्ना (राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकास पार्टी), मो. शमी (एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, मुस्लिम लीग), कृपाशंकर सविता (अध्यक्ष), सविता सल्मानी (समाज महासभा), अवधेश कुमार वर्मा, एस. पी. सिंह, शैलेंद्र भारती, रामसजीवन, रामबृज रावत, बिहारी लाल, रघुनंदन, कैलाशनाथ, उमाशंकर, विनोद रावत, शिवकुमार गौतम, केदारनाथ, राकेश बहादुर, कर्मवीर सिंह, के. आर. गौतम, अंगूरी धारिया, राजा कैलाश, श्रीराम, दिलीप रावत, नीरज चक, अश्विनी कुमार गौतम एवं अन्य उपस्थित थे।

सम्मेलन के अंत में केदारनाथ में आयी विपदा में मारे गये लोगों के लिए शोक श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा गया तथा आपदा में ऐसे लोगों को सेना द्वारा बचाने के लिए सेना की प्रशंसा करते हुए सेना को सभी लोगों ने सलाम किया।



## निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए आगामी 25 नवंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में अजा/जजा परिसंघ की रैली

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आवाहन पर 25 नवंबर, 2013 को प्रातः 10 बजे, रामलीला मैदान, नई दिल्ली में गत् वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुख्य रूप से निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए विशाल रैली का आवाहन किया जा रहा है। सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अतिशीघ्र प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाएं। जिले व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी रैली की तैयारी के संबंध में समा इत्यादि करना शुरू कर दें एवं की गई कार्यवाही से समय-समय पर राष्ट्रीय कार्यालय को भी अवगत कराएं। इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 011-23354841, 23354842, 23354843 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- डॉ० उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

## आगामी 25 अगस्त को लखनऊ में प्रांतीय सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की 30प्र0 इकाई का प्रांतीय सम्मेलन 25 अगस्त, 2013 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, सहकारिता भवन, लखनऊ में निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, सेना एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ० उदित राज जी होंगे। इस सम्मेलन को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी सम्बोधित करेंगे। 30प्र0 के विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व समाजसेवियों को सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया साथियों सहित उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाएं।



**भवननाथ पासवान**  
प्रदेश अध्यक्ष  
09415158866

# अंधभक्ति है या धर्म

डॉ. उदित राज

14 जून को उत्तराखंड में बादल फटे और प्रलय जैसी परिस्थिति पैदा हो गई। इसकी वजह से जगह-जगह पहाड़ की चट्टानें टूटी, रोड पर अवरोध हुआ और दरारें पड़ने के साथ-साथ सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गए, बारिश लगातार होती रही, ज्यादातर समय अंधेरा ही छाया रहा, सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मकान भी नहीं बचे, ऐसे में लाखों लोग फंस गए और सैकड़ों मर गए। खबरिया चैनल ने पूरे जोश के साथ मैदान संभाला और अभी भी मैदान में हैं। स्थानीय प्रशासन की वश की बात नहीं दिखी तो सेना को बुलाना ही था। लगातार विकास को कोसा जाता रहा कि बांधों से इतना बड़ा जलवायु में परिवर्तन आया है। ये भी कहा गया कि सरकारी विभागों के अधिकारियों की अनियमितताओं की वजह से

मंदिरों, धर्मशालाओं को बनने दिया? मान लिया जाए कि सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाना भी चाहते थे तो क्या वे ऐसा कर सकते थे? धर्म के नाम पर मंदिर-मस्जिद कहीं भी बन जाता है और सरकारी अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि वे उसे रोक सकें क्यों कि यह मामला आस्था का है? आस्था के नाम पर बहुत सारे खून माफ हैं। रातों-रात मंदिर बन जाते हैं और मूर्ति स्थापित हो जाती है तो क्या किसी की हिम्मत होती है कि कोई उसे हटा दें? मान लिया जाए कि राजनैतिज्ञ व सरकारी विभाग नालायक होते हैं तो क्या अभी तक किसी टीवी चैनल ने ऐसे मंदिरों, मस्जिदों के निर्माण पर कोई सनसनीखेज खबर दिखाया? हजारों करोड़ रूपए मंदिरों पर चढ़ावा आता है तो क्या इन्होंने प्रस्ताव रखा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि का निर्माण उसी पैसे से करेंगे? क्या मीडिया ने इस प्रश्न को देश के सामने रखा?

घुमाने से सब ठीक हो जाएगा। यह बात जरूर है ज्यादातर राजनीतिज्ञ व अधिकारी भ्रष्ट हैं लेकिन जनता को अपनी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

जब भगवान सर्वत्र है तो क्या उसका दर्शन केदारनाथ, बद्रीनाथ और जोशीमठ में ही होगा? क्या भगवान को एक विशेष समय पर पूजा-पाठ करने से लाभ होता है, यदि हां तो इसका मतलब ईश्वर भी मूछी है या उसको नियंत्रित करने वाली और भी कोई बाह्य शक्ति है। ईश्वर को तो सर्वत्र एवं समता में होना चाहिए। धर्म की परिभाषा इंसान और ईश्वर के बीच की चेतना की स्थिति है। उसे लड्डू, चुनरी, कपड़ा, नारियल, फूल, मुर्गा, दारू, सोना, चांदी, हीरा, चादर इत्यादि चढ़ा या देकर के कुछ प्राप्ति की सोच या चाहत रिश्वत नहीं तो क्या है? अपने आप को दंडित करके अर्थात् ज्यादा से ज्यादा तप और तपस्या करके ही भगवान के आर्शीवाद को प्राप्त किया



जाता, टिहरी डैम ने ही उसे बचाया। भागीरथ का पानी यदि टिहरी डैम ने न रोका होता तो पूरा ऋषिकेश स्वाहा हो गया होता। जो धर्माचार्य इस समय बांध बनने की आलोचना कर रहे हैं, ऋषिकेश बने इनके सारे आश्रम बह गए होते। हुआ यह कि टिहरी डैम में पानी का



अखबार के माध्यम से पानी पी-पीकर विज्ञान को कोस रहे हैं जबकि इसे विज्ञान ने ही बनाया है अर्थात् विज्ञान का पतित फल हेलीकॉप्टर, मोबाइल, टीवी, आदि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गंगा पर बांध बनने को मुख्य कारण माना जा रहा है जबकि भायंकर प्रलय जो ऋषिकेश और हरिद्वार को बहा ले

स्तर काफी कम था और भागीरथी से पानी चला उसका 95 प्रतिशत पानी वहीं रुक गया, वरना ऋषिकेश क्या हरिद्वार भी बह गया होता। धर्माचार्यों की शक्ति कहां गई? क्यों नहीं उनकी शक्ति ने लोगों को बचाया? अंधविश्वास की हद है कि केदारनाथ में कहा जा रहा है धारी देवी की मूर्ति हटा दी गई इसलिए वहां गंगा नाराज हो गई और यह तबाही हुई। प्रलय तो आदिकाल से ही चले आ रहे हैं और इससे कहीं कई गुणा बड़े रहे हैं। इस बार सरोवर का हिम पिघला और वह तबाही का बड़ा कारण बना। ज्यादा धर्मशाला, घर, सड़क, श्रद्धालु, बांध, गाड़ी आदि सभी जिम्मेदार हैं न कि केवल उपभोक्तावाद, बढ़ती जनसंख्या, बांध इत्यादि। इस समय न तो इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहिए और न ही एकपक्षीय तथ्य को रखा जाए, अंधविश्वास को धर्म न माना जाए और वही एक उपाय है न कि जिस तरह से इस समय अपने-अपने पक्षों को बढ़ा-चढ़ाकर के प्रस्तुत करके वातावरण खराब करने का।

इमारतों का अवैध निर्माण हुआ जिसकी वजह से न केवल जलवायु प्रभावित हुई बल्कि इन्हें असुरक्षित भी बनाया। ये कारण तो हैं लेकिन धर्मांधता के नाम पर और असली वजहों पर किसी ने टीका-टिप्पणी नहीं की। यह बात तो स्थापित हो गई है कि ज्यादातर समस्याओं के लिए मीडिया और आम लोग राजनैतिज्ञों एवं सरकारी विभागों को जिम्मेदार ठहराते हैं।

यह बड़ी आपदा है इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, भारी जान-माल की क्षति हुई है। ज्यादातर मौतें इसलिए हुई कि होटल और मकान के निर्माण की नींव कमजोर थी या पीछे की तरफ की ढलान पर जो नींव या आधार रखे गए, वह बेहद ही लचीले और कमजोर थे। यहां पर सवाल उठता है कि सरकार के विभिन्न विभाग क्या कर रहे थे? विकास प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? भूविज्ञान विशेषज्ञों से सलाह क्यों नहीं ली गई? भूकंप रहित ढांचा के बगैर क्यों

वहां की प्रकृति को खतरा विज्ञान से है तो ऐसे में धर्माचार्य सरकार को निमंत्रण दें कि हजारों करोड़ रूपए मंदिर के चढ़ावे से स्वयं इन क्षेत्रों का विकास करेंगे। तमाम और विषयों पर मीडिया शुरू से लेकर अंत तक ब्योरावार बात को रखती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे मामलों में भी कभी वह कर पाती है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि हर 5-10 मिनट पर खबरिया चैनल सरकार को गलत बता रहे हैं और यह भी कहना नहीं भूलते कि क्या किया जाए या क्या नहीं। विभिन्न दलों के नेताओं ने क्या किया, क्या कहा वह मुख्य खबर होती है। यदि कोई मामूली सी विवादित बात हो तो जो जान-माल की क्षति है उसे भी भूल जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जोशीमठ आदि पर जो कहर बरपा, वह निश्चित तौर से बेहद दुःखद है। लेकिन पुजारियों एवं श्रद्धालुओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्या वे निभाते हैं? सरकार वह कौन सी जादू है कि जिसकी छड़ी

जा सकता है। ये कैसा भगवान है जो अपने भक्तों का कष्ट देखकर के खुश होता है। इंसान झूठ ना बोले, भ्रष्टाचार से मुक्त रहे और देश और इंसान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाये तो क्या इससे भगवान खुश नहीं होते? दर्शन करने का समय और काल निश्चित होने की वजह से हजारों-लाखों लोग एक ही बार दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और इसी वजह से व्यवस्था चरमरा जाती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर अनगिनत कमजोर मकान और धर्मशाला बनते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी की धारा को ये इमारतें झेल नहीं सकी। यदि श्रद्धालुओं को यह ना बताया जाए कि एक निश्चित काल व समय पर उनके भक्ति का लाभ मिलने वाला है तो यह सिलसिला पूरे साल चलता रहे, तो न तो इतने धर्मशाला और घर बनाने की जरूरत पड़ेगी और न ही भीड़भाड़। वातावरण पर प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ेगा।

धर्माचार्य टेलीविजन और

## पाठकों से अपील

‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉप्ट द्वारा ‘जस्टिस पब्लिकेशंस’ के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क ‘जस्टिस पब्लिकेशंस’ के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया ‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास ‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रूपए  
एक वर्ष : 150 रूपए



# Odisha State Conference Held at Bhubaneswar

**Dilip K. Behera**

The State Conference of Odisha Unit of the All India Confederation of SC/ST Organisations, New Delhi, was held at Red Cross Bhawan, Bhubaneswar, Odisha, under the leadership of Shri Dillip Kumar Behera, State President, Odisha Unit and National General Secretary and State General Secretary Shri G.C. Dalei. Dr. Udit Raj Hon'ble National Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organisations, was kind enough to grace the occasion as Chief Guest. Mr. B.N. Swain, Executive Director of NALCO, Mr. Indramani Nahak representative of RBI, Mr. Gangadhar Sethi, Representative of Odisha Gramin Bank along with Allek Mallick were the Guests of Honour. The auditorium of Red - Cross Bhawan was jam-packed by the delegates from every nook & corner of Odisha. A large number of State Govt. and Central Govt. public sector & private sector employees and officers of Odisha Government had participated in the meeting. It was a spectacular achievement on the part of

the leaders of Odisha State Unit of the Confederation for exhibiting such a remarkable show which was appreciated by Hon'ble National Chairman Dr. Udit Raj. Shri G.C. Dalei gave brief details of the activities of the confederation. Thereafter the podium was handed over to Shri D.K. Behera to preside over the meeting and start the proceedings. The State President Shri D.K. Behera highlighted the activities of the Confederation in general and contribution of Dr. Udit Raj, in particular, for the welfare of SC/ST employees and Officers in connection including his contribution for withdrawal of anti-reservation orders of DOPT. After this, Dr. K.C. Mallick, Chairman of BISWA (Bharat Integrated Social Welfare Agency) Sambalpur, Odisha, was felicitated by Dr. Udit Raj for his stupendous achievement by rendering services to 42 lakh poor families for providing them employment opportunities. Dr. Udit Raj appreciated Dr. K. C. Mallick, a prominent dalit entrepreneur and his NGO called BISWA, a leading State level organization.

As soon as the inaugural

function was over, Shri D.K. Behera requested Dr. Udit Raj to express his views for which all the delegates were eagerly waiting. There was pin-drop silence in the conference when Dr. Udit Raj started his speech after welcoming all the delegates. At the very outset he spoke about 33 crore Hindu Gods and Goddesses with a comparative statement of their contribution towards human society with special reference to Hinduism. When India got freedom the population of SC/ST people was about 11 crore and if three gods and goddesses on an average would have uplifted one dalit, all of them would have been liberated from the bondage. Though all of them could not be uplifted by the endeavour of Dr. B. R. Ambedkar, yet millions could get dignified and prosperous living. Dr. Ambedkar gave haven to many in the present lives but Hinduism promises it after death which is never verifiable and not true. It is painful that many SC/ST Employees believe that their betterment in their lives has come due to the grace of these gods and hardly participate in the mission of social justice. He highlighted the indoor activities of paper-

head SC/ST organisations and corruption with special reference to Anna Hazare and Arvind Kejriwal. He made the audience spell-bound by mentioning that 85% of the people are being ruled by 15% of upper caste people. He concluded speech by encouraging all the participants to strengthen the State Confederation of Odisha to lofty heights of glory in future. He expressed his happiness at the huge gathering in the conference. Also he focused on reservation in Government Services and reservation in private sector. Apart from that, he stressed on how upper caste people being biased and prejudiced wrongly branded Dr. Udit Raj as an agent of BJP and Congress. In addition to that he also emphasized on the activities of BSP and BAMCEF.

He also expressed his views on the issue corruption with special reference to Anna Hazare and Arvind Kejriwal, over and above he made the audience spell bound how 85% of people are being ruled by 15% of upper caste people. He concluded his speech encouraging all the participants to strengthen the Odisha State confederation to

lofty heights of glory in future. He expressed his happiness at the huge gathering at the Conference.

State leaders as well as District leaders namely K.K. Sethi, S.K. Khanda, Purna Singh, Hiralal Sahu from Keonjhar Baripada, Balesore and Bailochan Seth, Bhagban Dandpat, A Tanti, R.P. Banchor, B. Sasoni, Shyam Oram, Krishna, Khirod Munda, Jagganath Sethi, Purna Chandra Bhoi, Muralidhar Das and others from Odisha Secretariat, Narayan Das along with his team were present in the meeting, Kumud Seth and Mrs. Kalpana Meher (Lecturer in History) were also present and expressed their happiness for the grand success of the meeting. Besides Sanjay Kumar Sahu along with his team of Indian Justice Party workers placed their unqualified support for the all-round development of the Confederation. There was short interval for lunch and thereafter again the after-noon session meeting started, which was concluded at about 6.30 P.M. Lastly Mr. Bansidhar Sethi from SBI was called upon to extend the vote of thanks to all the dignitaries and other participants.

## West Bengal Unit of Confederation constituted

June 23, 2013. A conference of West Bengal Unit of the All India Confederation of SC/ST Organisations was held at Ashutosh Birth Centenary Hall, Kolkata, to constitute the State and District Committee of West Bengal Unit of the All India Confederation of SC/ST Organizations. Dr. Udit Raj, Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organisations said that we have to continue our struggle for reservation in the private sector. He further said that the SC/ST people have suffered for centuries and now time has come when we should work for a casteless society. Many people from the upper caste are against reservation in Government jobs but we should not forget that it is because of this reservation, SC/ST people have got ample opportunities to get Government jobs at different levels. Dr. Udit Raj

also said that due to the untiring efforts of Dr. B.R. Ambedkar, reservation for SC/ST people had been secured but the most unfortunate thing is that the SC/ST people who are senior position in Government jobs because of the reservation policy, are neglecting the interests of their fellow brethren. In the end, Dr. Udit Raj said that the All India Confederation of SC/ST Organizations will organise a massive rally for demanding the reservation of SC, ST people in the private sector in Delhi on 25th Nov., 2013. The West Bengal state and district committee of the All India Confederation of SC/ST Organizations was formed for the period 2013 to 2016. Mr. Kamal Krishna Mondal was selected as president and Mr. Swapan Kumar Halder was selected as state general secretary of West Bengal Unit of the Confederation.

### Names of the Office Bearers of the newly constituted state unit

Shri Rameswar Ram	:	Patron
Shri Kamal Krishna Mandal	:	State President
Shri Basudeb Mondal	:	Vice President
Shri E.V. Raju	:	Vice President
Shri Promed Kumar	:	Vice President
Shri Bhaskar Chandra Naskar	:	Vice President
Shri Dilip Kumar Sheet	:	Vice President
Shri Chandra Pal Balmiki	:	Vice President
Dr. Tapati Mondal	:	Vice President
Shri Swapan Kumar Halder	:	General Secretary
Shri Sajal Kumar Mallick	:	State Secretary
Shri Arun Kumar Hansda	:	State Secretary
Shri Sourav Kumar Barman	:	State Secretary
Shri Ramasish	:	State Secretary
Shri Dulal Sarkar	:	State Secretary
Shri Sujit Balmiki	:	State Secretary
Shri Sanjoy Kirtonia	:	State Treasurer
Shri Jaydev Mondal	:	Asst Treasurer

#### Committee Member:-

Shri Milon Kr Hati, Shri Rahit Das, Shri Sachin Bauri, Shri Basant Rought, Shri S. N. Bera, Shri Shabundhu Saha, Shri Shiv Kr Mali, Smt. Shima Rani Sheet, Smt. Uma Shaw, Shri K. Lokeswar Row, Shri Khokan Sardar, Shri Rajen Gambheer

# I AM CONDEMNED FOR SPEAKING THE TRUTH – UDIT RAJ

Dr. Udit Raj

If Ms Mayawati adopts a democratic way of functioning, then her party can easily get 70 to 100 seats in the Lok Sabha. For this purpose, she has to change her way of working. Just like other leaders who frequently inter-act with party workers, MLAs and MPs and seek their opinions and suggestions, she should also act in the similar way. Employees and officers in Government organizations and PSUs are the back-bone of Dalit community. They are the one who are in a position to render some service to the community while not asking for much in return because financially they are self-dependent. Occasionally when they are discriminated, we have to listen to their grievance and try to resolve it. BSP is a national party and like BJP and Congress, why

should it not hold press conferences everyday? Atrocities and rapes have become a daily feature, reservation policy is not followed in its entirety, there is discrimination in transfers and postings, wrong policies are framed and if all these issues are raised with the Media on a regular basis, the affected people can get a lot of relief. Delhi University Vice-Chancellor has introduced the four-year under-graduate programme. Dalit and Backwards teachers, students and intellectuals tried their best to seek an appointment with Ms Mayawati so that they could apprise her of the fact that due to this policy, doors to higher education are being closed for Dalits and Backwards. BJP, CPM, JD(U), LJP, CPI, etc leaders not only met Dalit/Backward teachers, students and intellectuals but openly opposed the introduction of the four-

year under-graduate programme. BJP Leader Arun Jaitley, in a letter to the HRD Minister, has demanded to put an embargo on this course. JD(U) leader Sharad Pawar has also done the same thing. CPI(M) leader Sita Ram Yechury has met the Prime Minister in this regard. A job which was supposed to have been done by Bahujan Samaj Party has been done by others. This is going to cause maximum damage to Dalits and Backwards. BSP has got about 40 MPs and if each one of them is given the freedom to act accordingly, then the atrocities on Dalits will reduce considerably and Dalits /Backwards will march forward speedily, their rights will be protected and wherever their share is lacking in different sectors, it could be bridged.

At present, condition of Dalit community is such that neither they are

patronized by their own parties nor by other national parties who have a grudge that they do not get Dalit votes and as such they should not work as in the past. Sometimes these parties even go to the extent of telling Dalits that they should go to BSP for resolving their grievances. Unfortunately BSP doors are found closed and MPs, MLAs and leaders do not have the guts to raise issues of the Dalit/Backward community. In these circumstances, where should these people go? I know BSP leaders will not be happy with my comments but it is a fact and the people who are feeling hurt by my statement should go and talk to the BSP Supremo and they will be able to know the reality. I know it fully well that not a single BSP leader or worker has the courage to go to Ms Mayawati and speak to her as suggested

by me. Whenever people go to these leaders for their problems, grievances and violation of their rights, their stock reply is that they will attend to all these problems when they come to power. Do the leaders of other parties tell the same to their workers? But BSP workers are really great as they do not revolt against Ms Mayawati. Thus it is the greatness of the BSP workers and not that of Ms Mayawati. If Ms Mayawati is ready to agree to my suggestions given above, then I am ready to cooperate with BSP in every way because it is in the interest of Dalit community. I am ready to make any sacrifice in the interest of Dalit community. Why does not a BSP leader or worker take up the cudgels to undertake this task in the interest of Dalit community?

## SC/ST/OBC CONFEDERATION COMMEMORATES 43rd SHAHEEDI DIWAS OF SHAHEED BHAGAT AMAR NATH JI

R. K. Kalsotra

Jammu 1st June 2013- J&K unit of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations, J&K Unit commemorated 43rd death anniversary of Shaheed Bhagat Amar Nath Ji on 1st of June 2013 at the Auditorium of Govt. College for Women, Gandhi Nagar, Jammu in which a large number of members of the civil society of the Confederation paid their homage to the great leader. A video of more than one hour duration on the life and people who shared stage with Bhagat Ji during his life time was also released by the Confederation which was watched by the participants with all adulations and appreciations. Mr. Tara Chand, Dy. CM of the state was the chief guest

while as the occasion witnessed the participation of Mr. Yash Pal Kundal, ex minister and MLA, Samba and various political and social leaders. A memorandum was also submitted to the chief guest in which primary demand was for installing a Shaheedi Samarak or a bridge in his name, chowk or gate be named after him with his statute placed before it so that the whole state, and the nation, comes to know about the immense contribution of Shaheed Bhagat Ji for these classes. While addressing the gathering Mr. R.K. Kalsotra, the President of State unit of the Confederation described Shaheed-e-Azam Bhagat Amar Nath Ji as a 'messiah' of the down trodden people of this state who sacrificed his precious life on 1st of June

1970 in Karan Park in front of Civil Secretariat, Jammu by resorting to 'Hunger Strike' on 23rd May 1970 for implementation of reservation in the state when the Govt. of the state had failed to provide reservation even after 22 long years had elapsed since independence. It was after his sacrifice that the Govt. woke up and provided reservation in the State.

Mr. Kalsotra exhorted the people to follow the footsteps of such great leader and the Confederation continues its struggle for installation of a Shaheedi Samarak for Bhagat Amar Nath Ji, to stop the dilution of Scheduled Tribe status by the rich and powerful for their own benefit, to implementation of the Mandal Commission report for 27% reservation for OBCs of the

state and reservation in private sector, Reservation in ReT, ReZ, ReS, Consolidated, contractual, Adhoc, Temporary, need basis in govt. corporations, J&K Bank, J&K Grameen Bank, Co-operative Banks, NRHM, SPOs, Anganwari workers and other departments, special recruitment drives for SC/ST/OBCs, Recruitment without SSRB and PSC should not be carried out, Maintenance of roster and roster based seniority and promotion thereon, Provide reservation in the Districts according to proportion of population of SC/ST's at District level for district cadre posts, reservation to SC/ST/OBCs for elevation to the High Court, Provide admission to SC/ST/OBC students in all educational

institutions without charging any admission fees, empowerment of SC/ST/OBC Advisory boards. The President further appealed to the government to take positive steps for amelioration of the lot of the SC/ST/OBCs of the state so that these deprived communities could be brought into the mainstream and play an active part in the nation building.

Mr. Tara Chand, the Deputy Chief Minister of the state while saying that the demands contained in memorandum were genuine but it shall take time for fulfillment of the demands made. However, he assured to fulfill the foremost demand raised in the memorandum in respect of Shaheed Bhagat

# Constitution of National SC/ST/OBC Students & Youth Front (NSOSYF)

One lakh students will be brought under the banner of this Front.

Some students and youths, belonging to Brahmin, Rajput and Vaishya castes, who constitute only 15% of the society, raised a big hue and cry in Delhi against corruption and rape. How is it that Dalits, Backwards, Minorities and others belonging to progressive groups cannot launch a struggle for their rights and self-respect. Different groups of students and youths from these communities are individually holding demonstrations for their rights but their impact is not visible on the surface nor is likely to be so. Main reason for this situation is that these groups have not got a national level leader. Under the leadership of Dr. Udit Raj, All India Confederation of SC/ST Organizations has been in existence for the last 15 years in a strong way. This is the only organization which has been raising burning issues and has been working like a permanent political party. If SC/ST/OBC students decide to associate themselves with the Confederation, then this premier organization will not only guide and educate them but will always stand by them in all their struggles. Struggle for reservation in private sector has been launched by the Confederation. The beneficiaries of this struggle will be students and youths and not the office bearers of the Confederation. It is because of the struggle of Confederation that three constitutional amendments will be adopted and reservation was saved as a result of which lakhs of SC/ST students and youths have reaped the fruits of reservation. If the students and youths launch their campaigns at School, College and University levels for their amenities and rights, can it be helpful in achieving goals of their lives? Will they be able to fulfil the dreams of their parents? Government jobs are shrinking fast and it is only through reservation in private sector that SC/ST students and youths who are in majority will be able to get jobs. At present, there is maximum scope of jobs in the private sector. Dreams of students and youths will be realized with the constitution of National SC/ST/OBC Students & Youth Front (NSOSYF). In the year 2013-14, one lakh students and

youths will be brought under the banner of this Front.

So far SC/ST students and youths have not got proper leadership and direction. Their approach is restricted to school and college problems like admission, hostel accommodation and scholarship. They cannot get even these demands fulfilled because they are not affiliated with any national level organization. Despite all these problems, students and youths can achieve their main goal of getting jobs. Even though they take less part in the

and youths, joining any walk of life, after coming out from schools and colleges will get a ready-made platform in the form of NSOSYF just as NSUI is to Congress. There are many students and youths from colleges and universities who have got brilliant ideas and energy but there is no parent organization under whose banner they can work and it is through the medium of the Confederation that a proper direction can be given to the society. If SC/ST students face any problems in any

achieved but this again is a half-truth. The number of Dalits, Adivasis and OBC educated people and youths has increased but the number of Government jobs has not increased in that proportion. In fact, the number of Government jobs has shrunk. Under these circumstances, despite the competitive skills achieved by Dalits, Adivasis and OBC educated people, only 4 to 5% of them could become IAS, IPS, Doctors, Engineers, Clerks, Stenos, Constables, Army men etc. and the rest will remain unemployed. At the national level, there is no organization to represent the interests of the communities which could propagate the ideals of Phule, Shahu and Dr. Ambedkar and there should be an organization which should prepare those SC/ST and OBC students, who are not able to qualify for the Government jobs for other fields including social and political leadership. There is now greater scope of jobs in the private sector and without reservation in the private sector, all the education and skills acquired by SC/ST/OBC people will become useless. People of these communities hardly take to trade and industry and the Confederation has now come to the view that even though a lot of development has already taken place in social and political fields and is further taking place, but now the time has come when steps should be taken to make progress in the economic field. NSOSYF will make significant contribution in this area so that the people of these

communities who are not successful in Govt jobs, social and political fields, can enter the world of trade and industry and realize their dreams.

In our history after Independence, no student wing of any political party has launched any struggle to resolve the problems of SC/ST/OBC students and youths. It is well known that most of the students of the political parties have been under the control of Manuvadis and even if it is so, why should they fight for our causes. The upper caste people have shown discrimination towards us for centuries and which is continuing even now and under these circumstances, it is imperative for us to make our own organization which has not been done till date. Some upper caste students are also Ambedkarites and progressive in their outlook and for them our doors shall always remain open.

Whosoever helps the one-lakh strong SC/ST/OBC students and youths Front called NSOSYF will be doing great service to these communities which we owe to them and must repay. Whosoever gets this information, should pass it to maximum number of SC/ST/OBC students and youths and persuade them to become members of NSOSYF. Everybody's contribution who has helped in raising a strong force of 1 lakh persons will be duly recognized.



activities at school, college and university level, but their main goal should be to affiliate themselves wholeheartedly with National SC/ST/OBC Students and Youth Front. Why the SC/ST/OBC students and youths cannot organize a much larger front as compared to the front organized by Anna Hazare and Kejriwal? Some youths and students are under the wrong impression that by launching a struggle by remaining in their own organizations, they can achieve big goals which is only a half-truth. Whether it is in the field of knowledge or any struggle, an organization can achieve its goal only if it is of the level of organizations like SFI, AISF, ABVP, ASUI etc. NSOSYF is being conceived on the lines of NSUI, student front of the Congress Party and BJP's ABVP. We can call our organization a parent organization also. Students

University, they can take advantage of the strength of NSOSYF and resolve their problems expeditiously. Students and youths can shed their intellectual inhibitions and use their knowledge and experience for the welfare of the society which will ultimately throw up political leaders from amongst them. In the present context, most of the SC/ST/OBC leaders believe in doing lip service because like the upper caste people, they do not have any national level organization where they could get acquire social and political knowledge and experience. It is no exaggeration to say that the most important task is to organize the younger generation which NSOSYF has undertaken upon itself to do.

For all types of competitions, some people have set up coaching institutes and presume that by imparting knowledge, welfare of students and youths can be

## Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of '**Justice Publications**' at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

### Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

# Confederation State Unit Dissolved, Reinvigoration Soon

R. K. Kalsotra

Srinagar : 16.06.2013: Shri R K Kalsotra, State President, J & K unit of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations addressed the media persons in Srinagar in which he apprised them of the issues of SC/ST/OBC's in the state. He stated that the J & K unit of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations, has been fighting for the protection and implementation of the Constitutional rights of the weaker sections in the state. It has, many achievements to its credit among which a few are : getting one step up reservation, promulgation of SRO 110, representation of SC/ST members in PSC/SSRB, enactment of Reservation Act, 2004, restoration of 8 percent reservation for SCs and enhancement of reservation in promotion for STs from 5 to 10 percent, implementation of profession based to caste based reservation for OBC's, inter district reservation for SCs, lowering of marks criteria for scholarship from 60 percent to 55 percent, and other government orders passed/rectified so that SC/ST/OBCs of the state are properly represented in public employment. The state unit has worked relentlessly, in conjunction with the national body at Delhi, over the past fifteen years to achieve goals set by the confederation at the state and national level. The legislators / ministers belonging to SC/ST/OBC communities cutting across party lines, various social & religious organisations, people from different sections of society, especially the cadre of confederation have supported its agenda but a lot more needs to be done for accomplishment of remaining goals and to meet new emerging challenges.

Those to be achieved are :

-Reservation in recruitment in all forms including regular appointments : Rehbar-e-Taleem, Rehbar-e-Zerat, Rehbar-e-Sehat, Consolidated, contractual, Adhoc, Temporary, need basis appointments in Govt. Corporations, J&K Bank, J&K Grameen Bank, Co-operative Banks, NRHM, SPO's, Anganwari workers and other departments, as they are subsequently regularized. To calculate pending backlog of over 60,000 posts in these departments and launch special recruitment drives for SC/ST/OBCs to fill up these posts.

-Reservation should be provided in private sector also.

-Recruitment without consulting SSRB and PSC should not be carried out. Stop adhoc recruitment and provide reservation to the fullest extent in direct recruitment.

-Maintenance of roster and roster based seniority and promotion thereon in the government departments and PSU's, clearance of backlog vacancies in promotions, SRO 110 of 2000 which nullified the Catch up rule, must be implemented in letter and spirit as also the 85th amendment Act of the Constitution of India. Maintenance of roster point seniority for senior level posts of KAS, Engineering, Education, and other equivalent posts as also to scrap SRO 481 of 2010 as it denies a fair chance to SC/ST/OBC candidates to be promoted as Sr. Lecturers.

-Provide reservation: in the Districts according to proportion of population of SC/ST's at District level for district cadre posts, however, till this is done, give 1st and 2nd chance to local SC/ST and 3rd chance to Inter District category candidate. Also 1st provisio to Section 3

of the Reservation Act, 2004, which seals total reservation to 50 percent, be deleted.

-In judiciary: reservation to SC/ST/OBCs for elevation to the High Court.

-Central budgetary allocation: for SC's and ST's for the year 2013-14 is Rs. 45000 crore and Rs. 21,000 crore respectively, consequently, the Confederation impresses upon the state to demand Rs. 2000 crore for SC's and Rs. 1000 crore for STs as its share for the state immediately so that it could be utilized from April 2013 itself for generating job avenues for these communities so that inclination of unemployed youth towards public employment is lessened. On similar lines, the state should provide 10 % (Rs.3800 crore) and 8% (Rs.3500 crore) share for ST's and SC's respectively from out of total state budgetary allocation for the year 2013-14. Accountability of utilization of funds under special component plans which are exclusively meant for income generating programs for SC/ST/OBC's and stopping diversion thereof for general purposes.

-Educational institutions & scholarships: Provide admission to SC/ST/OBC students in all educational institutions without charging any admission fees and abolish marks criteria and income slab for entitlement of scholarships.

-SC/ST/OBC Advisory boards: must be empowered so that the purpose for which they are constituted is achieved.

- Implementation of 27% reservation for OBC's: as promised by ex-CM of the state as per the recommendations of the Mandal Commission report duly confirmed by the Hon'ble Supreme Court in Indira Sawhney's case. Further, the Confederation demands enhancement of income slab at par with that

at the centre for creamy layer.

- Adequate representation: to SC/ST/OBC students in all universities and Medical colleges.

- Stoppage of ST status and misclassification of OBC status.

-Provide full reservation quota: to SC/ST/OBC's @ 8/10/27 Percent respectively to the candidates in admission to PG Medical courses.

-Provide adequate representation: to the SC/ST/OBC categories in local body elections at Sarpanch, Urban local bodies and Block Development Council levels, secondly, to see to it that any law, rule or instruction, that goes against the rights of the SC/ST/OBCs of the state, may not be passed to the detriment of these categories.

- Political reservation: to Scheduled Tribes.

-Provide Hostel facilities: to SC/ST/OBC students at Tehsil levels so that rate of drop outs in schools/colleges is minimized.

-Conversion of seasonal centers for nomadic tribes into mobile schools.

-Extension of the jurisdiction: of the National Commission for SCs, National Commission for STs and National Commission for Backward Classes to the state of J&K by amendment in the respective state acts.

-Ban on manual scavenging: Rehabilitation of manual scavengers belonging to Watal Communities and confer OBC Status to these communities.

-Representation in PSC/SSRB: to SC members.

- Representation of SC/ST in: Legislative council and parliamentary seats.

-Provide Permanent resident rights: to the Refugees and to Valmiki community / Safai

Karamcharis who were brought to the state from Punjab in the hour of crisis in 1957 by the then Prime Minister Late Jenab Bakshi Ghulam Mohd. Also, promotion avenues for safai karamcharis be opened in a fair and impartial manner.

In the light of above stated goals, the Confederation vies for and has followed the path carved by Bharat Ratna Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar with his inimitable mantra to 'Educate' and 'Organize' the people to 'Agitate' for constitutional rights.

To provide an impetus, to reinvigorate and to decentralize the confederation to the lowest rung, the President, Mr. R. K. Kalsotra, All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations (J&K), in consultation with the National Chairman Dr. Udit Raj, has dissolved the state unit, Provincial Units, District Units and Tehsil units alongwith all student bodies and coordinators working under the umbrella of the Confederation pending reconstitution of new body. Fresh membership has been launched to elect new office bearers and representatives will be elected for the State, Provincial, District, Block, Tehsil and Village levels within shortest possible time to accomplish the goals. Honorary membership can be obtained by persons belonging to social, religious, persons of political fields, individuals etc.

The conclave was widely attended by the members of all the district, tehsil and block units of Kashmir, wherein the decision of State President and National Chairman was accepted in one voice and they all agreed to work for the cause of empowerment of SC/ST/OBC people of the state.

Rest of Page 5 ...

## SC/ST/OBC CONFEDERATION COMMEMORATES 43rd SHAHEDI DIWAS OF SHAHEED BHAGAT AMAR NATH JI

Amar Nath ji in the shortest possible time. Laying stress on similar seminars to educate people, the chief guest called upon the people to support and follow the path carved by Bhagat Ji. He further said that outside the legislature it must keep on its good works and inside the legislature they were there to take care of their rights. He further said that he has always supported the cause of the downtrodden and will continue to do so.

Mr Yash Pal Kundal, MLA Samba appreciated the endeavors of confederation to struggle for the upliftment of the SC/ST/OBCs of the state. He further laid stress on the unity of these classes under the common umbrella of the confederation assuring his full support to the cause Confederation has taken up.



# VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16

● Issue 15

● Fortnightly

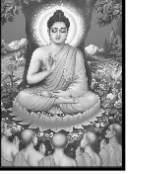
● Bi-lingual

● 16 to 30 June, 2013



## मादक पदार्थों का सेवन न करें

-गौतम बुद्ध



# Demonstration held at Jantar-Mantar against FYUP

The Joint Action Front for Democratic Education (SC/ST/OBC/Left) (JAFDE) held a demonstration on 22nd June, 2013 at Jantar Mantar to demand from the Govt. to stop the implementation of four year undergraduate programme (FYUP) that is going to be introduced in Delhi University. This large gathering was addressed by Ram Vilas Paswan, Dr. Udit Raj, Abha Dev, Hany Babu, Subhashini Ali and Nilotpal Basu (CPM). Shri Ram Vilas Paswan said that the reply from Prime Minister has come in this respect but, so far, no action has been initiated. How come Delhi University was implementing it silently and people came to know late. It is such a important thing that even he was not aware. Subhashini Ali held the view that women will be affected most if FYUP is implemented and this exposes the hypocrisy of the government to universalize the education among girl children. Nilotpal Basu opined that poor will be hit hard and they will be excluded from Higher Education in the days to come. He, however, emphasized that matter should be discussed in the Parliament.

No longer it is now confined to Delhi University rather the civil society is taking lead and has vowed to fight till FYUP is not scrapped. FYUP violates the national education policy of 1986 adopted by Parliament and



Ram Vilas Paswan and Dr. Udit Raj at the dais on the occasion of demonstration against FYUP at Jantar-Mantar

how a vice chancellor can change it from 10+2+3 to 10+2+3? It is surprising the Congress led Government is not honoring the policy ushered in by its own leader, the late Shri Rajiv Gandhi. The argument offered by the Vice-Chancellor that it is a matter of University autonomy is totally baseless and fraudulent. Rather the VC has encroached on the authority of the Parliament.

Dr Udit Raj, convener of JAFDE, said that we are compelled to go for nationwide agitation as the Govt. is not heeding our demands. Today's

demonstration has proved that not only students and teachers are part of this movement but outside society like dalits, backwards and social & political workers are equally agitated against the FYUP. He expressed that given the opportunity about the various programmes and policies to uplift the people, the most important would be education. Education is the key to take forward the country ahead. We fail to understand how the Government is being misled by one Vice-Chancellor and ignoring the voices of people from all walks of life and

specifically SC, ST, and OBC. Most of the political parties like BJP, LJP, JD(U), CPI(M), and CPI have taken a stand against FYUP for these reasons: how the holders of three years degree from other universities will get admission in DU and how the holders of four-year degree from DU will pursue further studies in other Indian universities; how will a four-year DU degree match with the three-year undergraduate degree in other Indian universities; the course contents of other universities will be different and how that will be reconciled; will it not

create discrimination in getting the jobs; will it not be difficult for rural and Indian languages background students to study compulsorily Maths, Science and English; will it not encourage inequality in the same degree with the multiple exit points, i.e., diploma at two years, bachelor at three and honors degree after four years. The idea of parity in higher education will be completely destroyed. Remember DU exists within the ambit of other central universities. Change can't be brought in this arbitrary, hasty, authoritarian manner.